



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड-21] रुड़की, शनिवार, दिनांक 16 मई, 2020 ई0 (बैशाख 26, 1942 शक सम्वत्) [संख्या-15

विषय-सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग-अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग-अलग खण्ड बन सकें

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
		रु0
सम्पूर्ण गजट का मूल्य ...	—	3075
भाग 1-विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस ...	217-225	1500
भाग 1-क-नियम, कार्य-विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया ...	223-230	1500
भाग 2-आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण ...	—	975
भाग 3-स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया ...	09-11	975
भाग 4-निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड ...	—	975
भाग 5-एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड ...	—	975
भाग 6-बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट ...	—	975
भाग 7-इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां ...	—	975
भाग 8-सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि ...	141-147	975
स्टोर्स पर्वेज-स्टोर्स पर्वेज विभाग का क्रोड़-पत्र आदि ...	—	1425

भाग 1

विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

आपदा प्रबन्धन अनुभाग-1

अधिसूचना

24 फरवरी, 2020 ई0

संख्या 51 / XVIII-B-1/2020-15(34) / 2013-राज्यपाल, उत्तराखण्ड आपदा न्यूनीकरण, प्रबन्धन तथा निवारण अधिनियम, 2005 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या-29, वर्ष 2005) की धारा 23 की उपधारा (1) सपठित धारा 13 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मानसून अवधि, 2019 में राज्य में घटित आपदाओं के कारण विशेष रूप से कृषकों को हुई क्षति से राहत दिये जाने के सम्बन्ध में निम्नलिखित जनपदों के तहसीलों के अन्तर्गत ग्रामों को आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

क्र.सं.	जनपद	तहसील	प्रभावित ग्राम का नाम
1	पिथौरागढ़	धारचूला	1-तांकुल 2-सिर्खा 3-सुवा
		तेजम	4-सेलमाली 5-मलोनी पन्द्रहपाला 6-कोटा 7- बाथीगूल 8-तल्ला भैसकोट 9-मल्ला भैसकोट 10-चामी भैसकोट 11-बसानी 12-खोली 13-कुतिमा 14-डोंगटी 15-पौथी 16-खेत भराड़
2	चमोली	थराली	1-फल्दिया 2-ओडर
		गैरसैण	3-चौरासैण 4-सारीगांव 5-पत्थरकट्टा
		चमोली	6-रोपा
		घाट	7-स्यारी बंगाली 8-धुर्मा

3	उत्तरकाशी	मोरी	1-डगोली 21-चिंवा 3-झोटाड़ी 4-धारा 5-दुचाणू 6-गोकुल 7-किराणू/मोल्डी 8-मोण्डा 9-माकुड़ी 10-आरकोट 11-कलीच 12-बलावट 13-बरनाली 14-जागटा 15-थापली 16-अडासू
---	-----------	------	---

आज्ञा से,
उत्पल कुमार सिंह,
मुख्य सचिव।

लोक निर्माण अनुभाग-1

कार्यालय ज्ञाप

24 फरवरी, 2020 ई0

संख्या 471/III(1)/20-04(21)/रि0या0/2019-मा0 लोक सेवा अधिकरण द्वारा क्लेम पिटीशन संख्या-28/डी0बी0/2019 में पारित आदेश दिनांक 05.07.2019 के अनुपालन में दिनांक 30.01.2018 को अधिशासी अभियन्ता (सिविल) से अधीक्षण अभियन्ता (सिविल) के पद पर हुई डी0पी0सी0 में श्री मयन पाल सिंह वर्मा "उत्तम" श्रेणी के अन्तर्गत वर्गीकृत होने के दृष्टिगत लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड में मौलिक रूप से नियुक्त श्री मयन पाल सिंह वर्मा, अधिशासी अभियन्ता (सिविल) को नियमित चयनोपरान्त उक्त डी0पी0सी0 दिनांक 30.01.2018 में चयनित श्री शिव कुमार राय की अधीक्षण अभियन्ता (सिविल) के पद पर पदोन्नति की तिथि दिनांक 06.02.2018 से श्री मयन पाल सिंह वर्मा को अधीक्षण अभियन्ता (सिविल) सातवें वेतनमान के वेतन मैट्रिक्स लेवल-13 के सादृश्य ₹ 37400-67000 ग्रेड वेतन ₹ 8700/- के पद पर नोशनल रूप से पदोन्नत करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उपरोक्त नोशनल पदोन्नति के फलस्वरूप श्री मयन पाल सिंह वर्मा को कोई ऐरियर देय नहीं होगा।

3- उपरोक्त पदोन्नति के फलस्वरूप श्री मयन पाल सिंह वर्मा अग्रिम आदेशों तक वर्तमान तैनाती के स्थान पर यथावत् रहेंगे।

आज्ञा से,
ओम प्रकाश,
अपर मुख्य सचिव।

बेसिक शिक्षा अनुभाग-2

अधिसूचना

19 फरवरी, 2020 ई0

संख्या 131/XXIV-A-2/45/2008 T.C. IV-राज्यपाल, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या-35, वर्ष 2009) की धारा 38 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तराखण्ड निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली, 2011 में अग्रेतर संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं, अर्थात् :-

उत्तराखण्ड निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (संशोधन) नियमावली, 2019

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ	1.	(1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम "उत्तराखण्ड निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (संशोधन) नियमावली, 2019" है। (2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।
नियम 16 का संशोधन	2.	उत्तराखण्ड निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली, 2011 में नियम 16 के उपनियम (3) के पश्चात् उपनियम (4), (5), (6) तथा (7) निम्नवत् अन्तः स्थापित कर दिये जायेंगे, अर्थात्:- (4) प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष के अन्त में कक्षा 05 एवं कक्षा 08 के लिए नियमित परीक्षा होगी। (5) यदि उप नियम (4) में उल्लिखित परीक्षा में बच्चा अनुत्तीर्ण होता है, तो उसे अतिरिक्त शिक्षण दिया जायेगा तथा परीक्षा परिणाम घोषित किये जाने की तिथि से दो माह के अन्तर्गत पुनः परीक्षा के अवसर निश्चित रूप से दिये जायेंगे। (6) यदि उपनियम (5) में उल्लिखित पुनः परीक्षा में भी बच्चा अनुत्तीर्ण होता है, तो खण्ड शिक्षा अधिकारी, राज्य सरकार की ओर से बच्चे को कक्षा 05 या कक्षा 08 या दोनों कक्षाओं में रोके जाने की अनुमति विद्यालय को दे सकते हैं।

		परन्तु खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण किये जाने तक बच्चे को किसी भी कक्षा में न रोके जाने पर निर्णय लिया जा सकेगा। (7) किसी भी बच्चे को प्रारम्भिक स्तर की शिक्षा पूर्ण करने पर विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।
--	--	--

आज्ञा से,

आर0 मीनाक्षी सुन्दरम्,
सचिव।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of "the Constitution of India", the Governor pleased to order the publication of the following English translation of Notification No. 131/XXIV/45/2008 T.C. IV, dated February 19, 2020 for general information.

NOTIFICATION

February 19, 2020

No. 131/XXIV/45/2008 T.C. IV--In exercise of the power conferred by Section 38 of the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 (Central Act No. 35 of 2009), the Governor is pleased to make the following rules with a view to further amend the Uttarakhand Right of Children to Free and Compulsory Education rules, 2011, namely :-

**The Uttarakhand Right of Children to Free and Compulsory Education
(Amendment) Rules, 2019**

Short title and Commencement	1.	(1) These Rules may be called the Uttarakhand Right of Children to Free and Compulsory Education (Amendment) Rules, 2019. (2) It shall come into force at once.
Amendment of Rule 16	2.	In the Right of Children to Free and Compulsory Education Rules 2011 after subrule (3) of Rule 16, the following sub-rule (4), (5), (6) and (7) shall be inserted, namely:-
		(4) There shall be a regular examination in the fifth class and in the eighth class at the end of every academic year.

			<p>(5) If a child fails in the examination referred to in sub-rule (4), he shall be given additional instruction and granted opportunity for re-examination within a period of two months from the date of declaration of the result.</p> <p>(6) The Block Education officer on behalf of state Government may allow School to hold back a child in the fifth class or in the eighth class or in both classes, if he fails in the re-examination referred to in sub-section (5):</p> <p>Provided that the Block Education officer may decide not to hold back a child in any class till the completion of elementary education.</p> <p>(7) No child shall be expelled from a school till the completion of elementary education."</p>
--	--	--	---

By Order,

R. MEENAKSHI SUNDARAM,

Secretary.

संस्कृति, धर्मस्व, तीर्थाटन प्रबन्धन एवं धार्मिक मेला अनुभाग

अधिसूचना

20 फरवरी, 2020 ई०

संख्या 115 / VI / 2020-83(7)2019 TC-I-उत्तराखण्ड चार धाम देवस्थानम् प्रबन्धन अधिनियम, 2019 की धारा-3 (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 20.02.2020 से उत्तराखण्ड राज्य में अवस्थित श्री बद्रीनाथ, श्री केदारनाथ, गंगोत्री एवं यमुनोत्री के प्रसिद्ध मन्दिर एवं अन्य मन्दिर समूहों की अवस्थापना सुविधाओं को विकसित करने, समुचित यात्रा-संचालन एवं प्रबन्धन हेतु चार धाम देवस्थानम् बोर्ड का निम्नानुसार गठन किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

बोर्ड के सदस्य:-**(क) शासकीय सदस्य-**

1. अध्यक्ष - मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड (यदि वह हिन्दू नहीं है तो मुख्यमंत्री द्वारा नामित हिन्दू धर्म को मानने वाला मंत्री परिषद् का वरिष्ठ मंत्री, जो बोर्ड के सदस्य के रूप में नियुक्त होने के लिए अर्हता रखता हो);
2. उपाध्यक्ष - संस्कृति और धार्मिक मामलों का मंत्री (यदि वह हिन्दू नहीं है तो मुख्यमंत्री द्वारा नामित मंत्री परिषद् का कोई वरिष्ठ मंत्री, जो हिन्दू धर्म का अनुयायी हो एवं बोर्ड के सदस्य के रूप में नियुक्त होने के लिए अर्हता रखता हो);
3. पदेन सदस्य - मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड सरकार;
- पदेन सदस्य - सचिव, पर्यटन विभाग, उत्तराखण्ड सरकार;
- पदेन सदस्य - सचिव, संस्कृति एवं धार्मिक मामलों का विभाग, उत्तराखण्ड सरकार;
- पदेन सदस्य - सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड सरकार;
4. संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार से विशेष आमंत्रित व्यक्ति जो कि संयुक्त सचिव की श्रेणी से निम्न न हो;
5. सदस्य सचिव - अधिनियम के अधीन नियुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी;

(ख) नामांकित सदस्य-

1. राज्य सरकार द्वारा नामित पूर्व टिहरी रियासत के राज परिवार का सदस्य या उसके द्वारा नामित व्यक्ति - एक;
2. राज्य सरकार की अनुशंसा पर संसद द्वारा नामांकित हिन्दू धर्म का अनुसरण करने वाले उत्तराखण्ड राज्य के सांसद - तीन से अनधिक;
3. राज्य सरकार की अनुशंसा पर हिन्दू धर्म का अनुसरण करने वाले राज्य विधान सभा के सदस्यों में से राज्य विधान सभा द्वारा नामित व्यक्ति - छः से अनधिक;
4. राज्य सरकार द्वारा नामित सदस्य जो दानदाता (भूत, वर्तमान या भविष्य) हो और हिन्दू धार्मिक मामलों में विशेष रुचि रखता हो - चार से अनधिक;

5. राज्य सरकार द्वारा नामित सनातन धर्म से सम्बन्धित हिन्दू धर्म के धार्मिक मामलों का व्यापक अनुभव रखने वाला ख्याति प्राप्त व्यक्ति - एक;
6. पुजारियों या वंशानुगत पुजारियों का प्रतिनिधित्व करने के लिये बट्टी-केदार, यमुनोत्री-गंगोत्री और अनुसूची में वर्णित मंदिरों में किसी अधिकार को धारण करने वाले ख्यातिप्राप्त व्यक्ति, राज्य सरकार द्वारा नामित - तीन;

आज्ञा से,
दिलीप जावलकर,
सचिव।

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-5

अधिसूचना

नियुक्ति

03 अप्रैल, 2020 ई0

संख्या 315/XXVIII(5)/2020-08(मे0का)/2019-उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा सेवा संवर्ग के अन्तर्गत सृजित/रिक्त पदों के सापेक्ष उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड द्वारा किये गये चयन के फलस्वरूप की गई संस्तुति के आधार पर श्री राज्यपाल महोदय, डॉ0 ओजस्वी शंकर पुत्री श्री शंकर लाल रामदास को राजकीय मेडिकल कालेज श्रीनगर हेतु असिस्टेन्ट प्रोफेसर (आब्स एण्ड गायनी) के पद पर वेतन मैट्रिक्स लेवल-11 वेतन ₹ 67,700-₹ 2,08,700 में निम्नलिखित शर्तों के अधीन अस्थाई रूप से नियुक्त करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

- (1) उल्लिखित अभ्यर्थी सम्बन्धित मेडिकल कालेज के प्राचार्य के समक्ष अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे। योगदान दिये जाने के पश्चात अभ्यर्थी के समस्त वांछित प्रपत्र/प्रमाण पत्रों का सत्यापन सम्बन्धित मेडिकल कालेज के प्राचार्य द्वारा कराया जायेगा।
- (2) चयनित असिस्टेन्ट प्रोफेसर का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन पृथक से सम्बन्धित मेडिकल कालेज के प्राचार्य द्वारा किया जायेगा। अभ्यर्थी की सत्यापन संबंधी रिपोर्ट शासन को उपलब्ध करायी जायेगी। यदि संबंधित असिस्टेन्ट प्रोफेसर का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सेवा में नियुक्ति हेतु उपयुक्त नहीं पाया जाता है, तो उनकी यह नियुक्ति तात्कालिक प्रभाव से निरस्त समझी जायेगी एवं इसकी सूचना तत्काल शासन को प्रेषित की जायेगी।
- (3) अभ्यर्थी अपने नियुक्ति पत्र सहित स्वास्थ्य परीक्षण हेतु सक्षम चिकित्सा अधिकारी के समक्ष उपस्थिति होंगे। स्वास्थ्य परीक्षण में अयोग्य घोषित किये गये अभ्यर्थी के प्रकरण शासन को संदर्भित किये जायेंगे।
- (4) नियुक्त असिस्टेन्ट प्रोफेसर को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अंतर्गत अनुमन्य मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते भी देय होंगे।

- (5) नवनियुक्त अभ्यर्थी 02 सप्ताह के भीतर अपने पद पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु योगदान कर दें। इस अवधि के भीतर वे अपने तैनाती से संबंधित वांछित सभी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेंगे। यदि वे इस अवधि के भीतर अपने योगदान स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन स्वतः समाप्त माना जायेगा।
- (6) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु अभ्यर्थी को किसी प्रकार का यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा।
- (7) अभ्यर्थियों को कार्यभार ग्रहण से पूर्व सम्बन्धित प्राचार्य के समक्ष निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे :-

- i. स्वयं के विरुद्ध अभियोजन न चलाये जाने तथा न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के संबंध में एक घोषणा-पत्र (संलग्न प्रारूप में)।
 - ii. उत्तराखण्ड मेडिकल काउन्सिल द्वारा निर्गत स्थाई पंजीकरण की दो प्रतियां।
 - iii. ओथ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।
 - iv. गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।
 - v. चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।
 - vi. लिखित रूप से एक अन्डरटेकिंग कि यदि चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन के पश्चात उन्हें सरकारी सेवा के लिए उपयुक्त नहीं पाया जाता है, तो उनकी यह नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी, जिसके लिए वे किसी क्षतिपूर्ति के हकदार नहीं होंगे।
 - vii. एक से अधिक जीवित पति/पत्नी न होने का घोषणा-पत्र (संलग्न प्रारूप में)।
 - viii. सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वस्थता प्रमाण-पत्र।
 - ix. दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण
- 2:- चिकित्सा शिक्षा सेवा संवर्ग में उक्त अभ्यर्थी की ज्येष्ठता उत्तराखण्ड, चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड से प्राप्त वरिष्ठता क्रम के आधार पर सुसंगत नियमों के अनुसार अवधारित की जायेगी।
 - 3:- असिस्टेन्ट प्रोफेसर के पद पर मौलिक रूप से नियुक्त अभ्यर्थी को उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा सेवा नियमावली-2014 में निहित प्राविधानों के अंतर्गत 02 वर्ष की विहित परिवीक्षा पर रखा जाता है।
 - 4:- सम्बन्धित मेडिकल कालेज के प्राचार्य द्वारा यह देख लिया जाए की अभ्यर्थी उत्तराखण्ड मेडिकल काउन्सिल में पंजीकृत है तथा उनके मेडिकल काउन्सिल प्रमाण-पत्र एवं स्नातक/स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा के प्रमाण-पत्र का मूल रूप से जांच कर, इन प्रमाण-पत्रों की दो-दो प्रतियां स्वयं प्रमाणित कर उत्तराखण्ड शासन एवं उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड को उपलब्ध कराया जाय।
 - 5:- उक्त नवनियुक्त असिस्टेन्ट प्रोफेसर की सेवा उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा सेवा नियमावली-2014 में निहित प्राविधानों के अंतर्गत राज्य के अन्य मेडिकल कालेजों में स्थानान्तरणीय होगी।

आज्ञा से,

नितेश कुमार झा,

सचिव।



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 16 मई, 2020 ई0 (बैशाख 26, 1942 शक सम्वत्)

भाग 1-क

नियम, कार्य-विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

HIGH COURT OF UTTARAKHAND, AT NAINITAL

NOTIFICATION

May 03, 2020

No. 92/UHC/Admin.B/2020--Having considered need of hearing in pending matters arising from urgency, and with a view to make procedure for hearing through Video Conferencing more convenient, in continuation with, and in partial modification of the High Court of Uttarakhand Notification No. 86/UHC/Admin.B/2020 dated 11.04.2020 read with Notification No. 89/UHC/Admin.B/2020 dated 18.04.2020 Hon'ble the Chief Justice is pleased to issue following directions to be applicable with immediate effect-

1. Apart from such other matters, which Hon'ble the Chief Justice deems fit and appropriate for urgent hearing through Video Conferencing, following types of cases, fresh or otherwise, will be processed for the urgent hearing through Video Conferencing, in the manner provided in the High Court of Uttarakhand Notification No. 86/UHC/Admin.B/2020, dated 11.04.2020 read with the Notification No. 89/UHC/Admin.B/2020, dated 18.04.2020--

- (A) Public Interest Litigations
- (B) Bail Applications
- (C) Criminal Appeals against conviction
- (D) Criminal Revisions against orders confirming conviction
- (E) Writ Petitions Criminal (WPCRL)
- (F) Writ Petitions (Habeas Corpus)

- (G) Writ Petitions seeking relief against eviction, ejectment, dispossession from property, or its demolition
- (H) Writ Petitions seeking relief against attachment, auction or any other similar legal recourse affecting the property.
2. Where, while requesting for the urgent hearing in the format prescribed in this regard, it is informed by the advocate that no further application, documents etc. are to be filed/e-mailed by him in such already pending matter like Bail Matter etc., and requests that for this reason, the matter be listed before the Court, as it is, and the prayer for urgent hearing through Video Conferencing in such matter is accepted by Hon'ble the Chief Justice, the matter be forthwith listed before such Bench, as may be constituted for that purpose.

By Orders of Hon'ble the Chief Justice,

HIRA SINGH BONAL,
Registrar General.

HIGH COURT OF UTTARAKHAND, NAINITAL

NOTIFICATION

May 04, 2020

No. 93/XIV-a/51/Admin.A/2012--Ms. Anita Kumari, Civil Judge (Sr. Div.), Pauri Garhwal is hereby sanctioned child care leave for 40 days w.e.f. 20.01.2020 to 28.02.2020 with permission to prefix 19.01.2020 as Sunday holiday, in terms of Office Memorandum No. 11/XXVII(7)34/2011 dated 30.05.2011 issued by Government of Uttarakhand.

NOTIFICATION

May 04, 2020

No. 94/XIV/a-39/Admin.A/2015--Sri Ravi Ranjan, Civil Judge (Jr. Div.), Khatima, District Udham Singh Nagar is hereby sanctioned paternity leave for 15 days w.e.f. 04.03.2020 to 18.03.2020, in terms of G.O. No. 819/XXXVII(7)34/2010-11 dated 31.12.2013.

NOTIFICATION

May 04, 2020

No. 95/XIV-a/40/Admin.A/2012--Sri Abhishek Kumar Srivastava, Civil Judge (Sr. Div.), Almora is hereby sanctioned earned leave for 11 days w.e.f. 11.03.2020 to 21.03.2020 with permission to prefix 08.03.2020 to 10.03.2020 as Sunday & Holi holidays and suffix 22.03.2020 as Sunday holiday.

By Order of Hon'ble the Administrative Judge,

Sd/-

Registrar (Inspection).

कार्यालय जनपद न्यायाधीश, पिथौरागढ़**कार्यभार मुक्त प्रमाण-पत्र**

07 फरवरी, 2020 ई0

11

पत्रांक 89/I-01-2019-प्रमाणित किया जाता है कि मेरे द्वारा सिविल जज (सीनियर डिवीजन), पिथौरागढ़ का कार्यभार माननीय उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल के परिपत्र संख्या 189/XIV/a-34/Admin.A/2013 दिनांक 08 जनवरी, 2020 के द्वारा दिनांक 10-02-2020 से दिनांक 10-03-2020 तक (दिनांक 08-02-2020 के द्वितीय शनिवार अवकाश व दिनांक 09-02-2020 के रविवार अवकाश को पूर्वयोजित एवं दिनांक 14-03-2020 के द्वितीय शनिवार अवकाश व दिनांक 15-03-2020 के रविवार अवकाश को पश्चात् योजित करते हुए) कुल तैंतीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत होने के फलस्वरूप आज दिनांक 07-02-2020 को अपराह्न में छोड़ा गया।

प्रतिहस्ताक्षरित,

ह0/- (अस्पष्ट)

जनपद न्यायाधीश,

पिथौरागढ़।

रश्मि गोयल,

सिविल जज (सीनियर डिवीजन),

पिथौरागढ़।

कार्यभार ग्रहण प्रमाण-पत्र

22 फरवरी, 2020 ई0

29

पत्रांक 121/2020-प्रमाणित किया जाता है कि माननीय उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल के पत्र संख्या 664/XIV/a-45/Admin.A/2017 दिनांकित 04 फरवरी, 2020 के अनुपालन में मेरे द्वारा दिनांक 10-02-2020 से दिनांक 20-02-2020 तक कुल 11 दिनों के अर्जित अवकाश, दिनांक 08-02-2020 एवं दिनांक 09-02-2020 के राजकीय अवकाश को पूर्वयोजित एवं दिनांक 21-02-2020 के महाशिवरात्रि अवकाश को पश्चात् योजित करते हुए, का उपभोग करने उपरान्त, आज दिनांक 22-02-2020 के पूर्वान्ह में सिविल जज (जूनियर डिवीजन)/न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी), गंगोलीहाट, जिला पिथौरागढ़ का पदभार ग्रहण कर लिया गया है।

प्रतिहस्ताक्षरित,

ह0/- (अस्पष्ट)

जनपद न्यायाधीश,

पिथौरागढ़।

अनिल कुमार कोरी,

सिविल जज (जू0डि0)/न्यायिक,

मजिस्ट्रेट (प्र0श्रे0), गंगोलीहाट।

कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, रुद्रप्रयाग

आदेश

14 फरवरी, 2020 ई0

संख्या 1039 (a)/प्रवर्तन/लाइसेन्स/2019-सर्वोच्च न्यायालय के अधीन गठित सड़क सुरक्षा समिति के सन्दर्भ संख्या 05/2014/सी0ओ0आरएस0 पार्ट-3 दिनांक 18-08-2015 सन्दर्भ संख्या 05/2014/सी0ओ0आरएस0 पार्ट-3 दिनांक 17-11-2015 के अनुपालन में मोटर वाहन अधिनियम के नियमों का उल्लंघन करने के विदित अभियोग में वाहनों के चालान कर वाहन चालकों के लाइसेन्स के विरुद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गयी है। अतः लाइसेन्सधारकों को उक्त सम्बन्ध में सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए एवं दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने व जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लाइसेन्सिंग अधिकारी, रुद्रप्रयाग के रूप में मैं डॉ संगीता भट्ट, प्र० सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, रुद्रप्रयाग मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा-19 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्न चालकों के लाइसेन्स तत्काल प्रभाव से निलंबित करती हूँ। उक्त अवधि में लाइसेन्स निलम्बित अवस्था में कार्यालय में जमा रहेगा। उक्त अवधि के पश्चात् लाइसेन्स अवमुक्त किया जायेगा :-

क्र० सं०	चालक का नाम व पता	डी०एल० संख्या व वैधता	अभियोग	चालानकर्ता प्रवर्तन अधिकारी	निलम्बन अवधि
1.	शाहताव पुत्र श्री मुराद अली मोहम्मदपुर पांडा, भगवानपुर, रुडकी पिन-247661	UK-0820140130117 VALIDITY (NT) 28.03.2034 VALIDITY (T) 24.07.2021	संकेत का पालन नहीं	ARTO RUDRAPRAYAG	14.02.2020 से 13.05.2020

आदेश

14 फरवरी, 2020 ई0

संख्या 1039/प्रवर्तन/लाइसेन्स/2019-सर्वोच्च न्यायालय के अधीन गठित सड़क सुरक्षा समिति के सन्दर्भ संख्या 05/2014/सी0ओ0आरएस0 पार्ट-3 दिनांक 18-08-2015 सन्दर्भ संख्या 05/2014/सी0ओ0आरएस0 पार्ट-3 दिनांक 17-11-2015 के अनुपालन में मोटर वाहन अधिनियम के नियमों का उल्लंघन करने के विदित अभियोग में वाहनों के चालान कर वाहन चालकों के लाइसेन्स के विरुद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गयी है। अतः लाइसेन्सधारकों को उक्त सम्बन्ध में सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए एवं दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने व जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लाइसेन्सिंग अधिकारी, रुद्रप्रयाग के रूप में मैं डॉ संगीता भट्ट, प्र० सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, रुद्रप्रयाग मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा-19 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्न चालकों के लाइसेन्स तत्काल प्रभाव से निलंबित करती हूँ। उक्त अवधि में लाइसेन्स निलम्बित अवस्था में कार्यालय में जमा रहेगा। उक्त अवधि के पश्चात् लाइसेन्स अवमुक्त किया जायेगा :-

क्र० सं०	चालक का नाम व पता	डी०एल० संख्या व वैधता	अभियोग	चालानकर्ता प्रवर्तन अधिकारी	निलम्बन अवधि
1.	श्री नितिन राणा पुत्र श्री दिनेश चंद्रा ग्राम जुआनी थाना नारायणकोटी जनपद रुद्रप्रयाग पिन-246171	UK-1320170012927 VALIDITY (NT) 27.10.2037	बिना हेलमेट वाहन का संचालन	SP CHAMOLI	14.02.2020 से 13.05.2020

आदेश

17 फरवरी, 2020 ई0

संख्या 1041 (a)/प्रवर्तन/लाइसेन्स/2019—सर्वोच्च न्यायालय के अधीन गठित सड़क सुरक्षा समिति के सन्दर्भ संख्या 05/2014/सी0ओ0आरएस0 पार्ट-3 दिनांक 18-08-2015 सन्दर्भ संख्या 05/2014/सी0ओ0आरएस0 पार्ट-3 दिनांक 17-11-2015 के अनुपालन में मोटर वाहन अधिनियम के नियमों का उल्लंघन करने के विदित अभियोग में वाहनों के चालान कर वाहन चालकों के लाइसेन्स के विरुद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गयी है। अतः लाइसेन्सधारकों को उक्त सम्बन्ध में सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए एवं दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने व जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लाइसेन्सिंग अधिकारी, रुद्रप्रयाग के रूप में मैं डॉ संगीता भट्ट, प्र० सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, रुद्रप्रयाग मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा-19 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्न चालकों के लाइसेन्स तत्काल प्रभाव से निलंबित करती हूँ। उक्त अवधि में लाइसेन्स निलम्बित अवस्था में कार्यालय में जमा रहेगा। उक्त अवधि के पश्चात् लाइसेन्स अवमुक्त किया जायेगा :-

क्र० सं०	चालक का नाम व पता	डी०एल० संख्या व वैधता	अभियोग	चालानकर्ता प्रवर्तन अधिकारी	निलम्बन अवधि
1.	श्री नरेन्द्र सिंह पुत्र श्री मुखला सिंह ग्राम डोभा उर्फ जाखल, जखोली जनपद रुद्रप्रयाग पिन-246475	UK-1320010000644 VALIDITY (NT) 22.12.2019	ओवरलोड सवारी (यात्री वाहन)	ARTO RUDRAPRAYAG	17.02.2020 से 16.05.2020
2.	श्री सुरजान सिंह पुत्र श्री हुकुम सिंह ग्राम कोट, जखोली रुद्रप्रयाग पिन-246475	UK-1320140006708 VALIDITY (NT) 22.12.2019	ओवरलोड सवारी (यात्री वाहन)	ARTO RUDRAPRAYAG	17.02.2020 से 16.05.2020

डॉ संगीता भट्ट,

प्र० सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी,

रुद्रप्रयाग।

आदेश

24 फरवरी, 2020 ई0

संख्या 1087/प्रवर्तन/लाइसेन्स/2019—सर्वोच्च न्यायालय के अधीन गठित सड़क सुरक्षा समिति के सन्दर्भ संख्या 05/2014/सी0ओ0आरएस0 पार्ट-3 दिनांक 18-08-2015 सन्दर्भ संख्या 05/2014/सी0ओ0आरएस0 पार्ट-3 दिनांक 17-11-2015 के अनुपालन में मोटर वाहन अधिनियम के नियमों का उल्लंघन करने के विदित अभियोग में वाहनों के चालान कर वाहन चालकों के लाइसेन्स के विरुद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गयी है। अतः लाइसेन्सधारकों को उक्त सम्बन्ध में सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए एवं दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने व जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लाइसेन्सिंग अधिकारी, रुद्रप्रयाग के रूप में मैं मोहित कुमार कोठारी, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, रुद्रप्रयाग मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा-19 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्न चालकों के लाइसेन्स तत्काल प्रभाव से निलंबित करता हूँ। उक्त अवधि में लाइसेन्स निलम्बित अवस्था में कार्यालय में जमा रहेगा। उक्त अवधि के पश्चात् लाइसेन्स अवमुक्त किया जायेगा :-

क्र० सं०	चालक का नाम व पता	डी०एल० संख्या व वैधता	अभियोग	चालानकर्ता प्रवर्तन अधिकारी	निलम्बन अवधि
1.	श्री योगेश चंद्र कप्रवाण पुत्र श्री केशवानंद कप्रवाण ग्राम सौण तल्ला, पट्टी चलनसू श्रीनगर जनपद पौड़ी गढ़वाल पिन-246174	UK-1220080004784 VALIDITY (NT) 03.06.2034 VALIDITY (T) 03.06.2020	ओवरलोड सवारी (यात्री वाहन)	ARTO RUDRAPRAYAG	24.02.2020 से 23.05.2020

मोहित कुमार कोठारी,
सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी,
रुद्रप्रयाग।

आदेश

20 फरवरी, 2020 ई०

संख्या 1068/प्रवर्तन/लाइसेन्स/2019-सर्वोच्च न्यायालय के अधीन गठित सड़क सुरक्षा समिति के सन्दर्भ संख्या 05/2014/सी०ओ०आर०एस० पार्ट-3 दिनांक 18-08-2015 सन्दर्भ संख्या 05/2014/सी०ओ०आर०एस० पार्ट-3 दिनांक 17-11-2015 के अनुपालन में मोटर वाहन अधिनियम के नियमों का उल्लंघन करने के विदित अभियोग में वाहनों के चालान कर वाहन चालकों के लाइसेन्स के विरुद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गयी है। अतः लाइसेन्सधारकों को उक्त सम्बन्ध में सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए एवं दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने व जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लाइसेन्सिंग अधिकारी, रुद्रप्रयाग के रूप में मैं डॉ संगीता भट्ट, प्र० सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, रुद्रप्रयाग मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा-19 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्न चालकों के लाइसेन्स तत्काल प्रभाव से निलंबित करती हूँ। उक्त अवधि में लाइसेन्स निलम्बित अवस्था में कार्यालय में जमा रहेगा। उक्त अवधि के पश्चात् लाइसेन्स अवमुक्त किया जायेगा :-

क्र० सं०	चालक का नाम व पता	डी०एल० संख्या व वैधता	अभियोग	चालानकर्ता प्रवर्तन अधिकारी	निलम्बन अवधि
1.	श्री प्रेम लाल पुत्र श्री मुरलीधर, ग्राम मैखंडा पो० फाटा, जनपद रुद्रप्रयाग	UK-1320160010748 VALIDITY (NT) 02.05.2023	नशे की हालत में वाहन का संचालन	SP TEHRI	20.02.2020 से 19.03.2015

डॉ संगीता भट्ट,
प्र० सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी,
रुद्रप्रयाग।

आदेश

27 फरवरी, 2020 ई०

संख्या 1089/प्रवर्तन/लाइसेन्स/2019—सर्वोच्च न्यायालय के अधीन गठित सड़क सुरक्षा समिति के सन्दर्भ संख्या 05/2014/सी०ओ०आर०एस० पार्ट-3 दिनांक 18-08-2015 सन्दर्भ संख्या 05/2014/सी०ओ०आर०एस० पार्ट-3 दिनांक 17-11-2015 के अनुपालन में मोटर वाहन अधिनियम के नियमों का उल्लंघन करने के विदित अभियोग में वाहनों के चालान कर वाहन चालकों के लाइसेन्स के विरुद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गयी है। अतः लाइसेन्सधारकों को उक्त सम्बन्ध में सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए एवं दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने व जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लाइसेन्सिंग अधिकारी, रुद्रप्रयाग के रूप में मैं सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, रुद्रप्रयाग मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा-19 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्न चालकों के लाइसेन्स तत्काल प्रभाव से निलम्बित करता हूँ। उक्त अवधि में लाइसेन्स निलम्बित अवस्था में कार्यालय में जमा रहेगा। उक्त अवधि के पश्चात् लाइसेन्स अवमुक्त किया जायेगा :-

क्र० सं०	चालक का नाम व पता	डी०एल० संख्या व वैधता	अभियोग	चालानकर्ता प्रवर्तन अधिकारी	निलम्बन अवधि
1.	खुशानसीब पुत्र श्री नीसार अहमद बहबलपुर हाशुवाला, हरिद्वार पिन-247661	UK-0820190001597 VALIDITY (NT) 07.03.2039	ओवरलोड सवारी (भार वाहन)	ARTO RUDRAPRAYAG	27.02.2020 से 23.05.2020
2.	शाहरुख पुत्र श्री जंगू ग्राम रामपुर, रुड़की हरिद्वार पिन-247667	UK-1720150008297 VALIDITY (NT) 14.06.2035 VALIDITY (T) 16.10.2019	ओवरलोड सवारी (भार वाहन)	ARTO RUDRAPRAYAG	27.02.2020 से 23.05.2020

सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी,
रुद्रप्रयाग।

कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, टनकपुर (चम्पावत)

आदेश

27 फरवरी, 2020 ई०

पत्रांक 254/पंजीयन निरस्त/2019-20—वाहन सं० UP030007(HGV) मॉडल 1989 चैचिस 363073318475 इंजन सं० 6921S01327967 इस कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन स्वामी श्री आलोक अग्रवाल पुत्र श्री जय श्याम अग्रवाल, निवासी जी०बी० पन्त मार्ग, वार्ड नम्बर 01 टनकपुर चम्पावत के नाम पंजीकृत है। दिनांक 14-02-2020 को वाहन स्वामी द्वारा वाहन के पंजीयन निरस्त हेतु (क्योंकि वाहन चलने योग्य नहीं है) आवेदन किया गया है। वाहन फाइनैन्स मुक्त है। प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चैक चालान लम्बित नहीं है। सीनियर फोरमैन (उत्तराखण्ड परिवहन निगम टनकपुर) की आख्यानुसार वाहन का मूल चैचिस प्लेट नष्ट कर जमा कर लिया गया है। उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन/चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः, मैं, विपिन कुमार सिंह, परिवहन कर अधिकारी-1, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी कार्यालय टनकपुर चम्पावत केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 55 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक UP030007(HGV) मॉडल 1989 चैचिस 363073318475 इंजन नं0 6921S01327967 को तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ।

विपिन कुमार सिंह,

परिवहन कर अधिकारी-1

सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी कार्यालय,

टनकपुर (चम्पावत)।



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 16 मई, 2020 ई0 (बैशाख 26, 1942 शक सम्वत्)

भाग 3

स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, नगर प्रशासन, नोटिफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया

कार्यालय पंचास्थानि चुनावालय, अल्मोड़ा

ग्राम पंचायतों के उप-प्रधानों का सामान्य निर्वाचन-2020

सूचना

19 फरवरी, 2020 ई0

संख्या 1014/उप प्रधान निर्वाचन/2020-राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड देहरादून की अधिसूचना सं0-4212/रा0नि0आ0अनु0-2/2836/2019 दिनांक 18 फरवरी, 2020 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में मैं, नितिन सिंह भदौरिया, जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) अल्मोड़ा जिले के समस्त 11 विकास खण्डों की समस्त ग्राम पंचायतों के उप प्रधानों का सामान्य निर्वाचन निम्नांकित विनिर्दिष्ट समयसारणी के अनुसार सूचित करता हूँ:-

नाम-निर्देशन पत्रों को जमा करने का दिनांक व समय	नाम-निर्देशन पत्रों की जांच का दिनांक व समय	नाम वापसी हेतु दिनांक व समय	निर्वाचन चिन्ह आवंटन का दिनांक व समय	मतदान का दिनांक व समय	मतगणना का दिनांक व समय
1	2	3	4	5	6
26.02.2020 (पूर्वाह्न 10:00 बजे से पूर्वाह्न 11:00 बजे तक)	26.02.2020 (पूर्वाह्न 11:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक)	26.02.2020 (दोपहर 12:00 बजे से अपराह्न 12:30 बजे तक)	26.02.2020 (अपराह्न 12:30 बजे से अपराह्न 01:00 बजे तक)	26.02.2020 अपराह्न 01:30 बजे से अपराह्न 03:30 बजे तक	26.02.2020 (अपराह्न 04:00 बजे से कार्य की समाप्ति तक)

2. उ0प्र0 पंचायतराज (सदस्यों, प्रधानों और उप-प्रधानों का निर्वाचन) नियमावली 1994/उ0प्र0 शासन पंचायती राज अनु-1 की अधिसूचना संख्या 2392/33-2-200-384/2000 दिनांक 11 अगस्त 200 द्वारा संशोधित) (उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त) के नियम 117-(1) में दी गयी व्यवस्था के अनुसार ग्राम पंचायत के संघटन से सम्बन्धित अधिसूचना जारी किये जाने के पश्चात आयोग की अधिसूचना में विनिर्दिष्ट तिथि को खण्ड विकास अधिकारी/नोडल अधिकारी द्वारा प्रत्येक ग्राम पंचायत हेतु नियुक्त किये गये निर्वाचन अधिकारी/मतदान अधिकारी सम्बन्धित विकास खण्ड की ग्राम पंचायत में उप प्रधान ग्राम पंचायत के निर्वाचन हेतु बैठक आहूत करेंगे। ग्राम पंचायत की बैठक ग्राम पंचायत के पंचायत भवन, यदि पंचायत भवन न हो तो ग्राम पंचायत में स्थित विद्यालय भवन अथवा धार्मिक स्थल को छोड़कर अन्य किसी सार्वजनिक स्थल पर ही आहूत की जायेगी, किसी व्यक्ति विशेष के निवास स्थान पर उक्त बैठक कदापि आहूत न की जायेगी।
3. उक्त संशोधित नियमावली के नियम 117(2) के अनुसार जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी की ओर से नोडल अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी इस निर्वाचन हेतु प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए एक निर्वाचन अधिकारी/मतदान अध्यक्ष नियुक्त करेंगे तथा नियुक्त किये गये निर्वाचन अधिकारियों की सूची अधोहस्ताक्षरी को प्रेषित करेंगे। उक्त निर्वाचन अधिकारी, ऐसा सहायक विकास अधिकारी, नायब तहसीलदार, कानूनगो, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी या कोई अन्य अधिकारी या कोई कर्मचारी हो सकता है नियुक्त किया जाय। परन्तु किसी ग्राम पंचायत विकास अधिकारी को अपनी तैनाती के ग्राम पंचायत में निर्वाचन अधिकारी नियुक्त नहीं किया जायेगा। उप प्रधान के निर्वाचन हेतु ग्राम पंचायत के सदस्यों की सूची "निर्वाचक सूची" (निर्वाचक नामावली) होगी।
4. उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम 1916 (यथासंशोधित, 2019) की धारा-10-ग(1) के अनुसार "उप-प्रधान ग्राम पंचायत के सदस्यों द्वारा अपने सदस्यों में से ऐसी रीति से निर्वाचित किया जायेगा जो नियत की जाय परन्तु यह कि यदि ग्राम पंचायत तदर्थ नियमों द्वारा या उसके अधीन नियत समय के भीतर उप प्रधान को इस प्रकार निर्वाचित करने में चूक करे तो नियत अधिकारी ग्राम पंचायत के किसी सदस्य को उप प्रधान के रूप में नाम निर्दिष्ट कर सकेगा और इस प्रकार नामनिर्दिष्ट व्यक्ति सम्यक रूप से निर्वाचित हुआ समझा जायेगा" का प्रावधान है अतः उपरोक्त व्यवस्था के अनुसार इस निर्वाचन में प्रधान को मत देने का अधिकार नहीं होगा।
5. राज्य निर्वाचन आयोग की अधिसूचना संख्या 191/रा.नि.आ./निर्वा.(33)/2001 दिनांक 30 अगस्त 2001 में उप प्रधानों के निर्वाचन हेतु अधिसूचित निर्वाचन प्रतीक चिन्ह ही उप प्रधानों के सामान्य निर्वाचन 2020 हेतु प्रयोग में लाये जायेंगे।
5. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा उपलब्ध कराये गये मतपत्र निर्वाचन के समय प्रत्याशियों की संख्या के अनुसार तैयार किये गये संख्या के प्रतीक चिन्ह ही मतपत्र में प्रयोग किये जायेंगे। आवंटित मतपत्रों को निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों की संख्या के अनुसार तैयार करने हेतु उनमें अनावश्यक निर्वाचन प्रतीक चिन्ह सफाई से काटकर अगल करने के पश्चात मतपत्र प्रयोग में लाये जायेंगे अर्थात् यदि प्रत्याशियों की संख्या से अधिक निर्वाचन चिन्ह मतपत्रों में हो तो शेष अतिरिक्त चिन्हों को मतपत्रों से काटकर छोटा कर लिया जाय परन्तु किसी भी दशा में मतपत्र मुद्रित क्रमांक को काटा अथवा नष्ट नहीं किया जायेगा।
6. उक्त निर्वाचन हेतु आयोग द्वारा आपूर्ति की गयी मतपेटी प्रयोग में लायी जायेगी।
7. उपलब्ध कराये जा रहे उप प्रधान के नाम निर्देशन पत्र परिशिष्ट-2(घ) में रिटर्निंग आफिसर का विनिश्चय दो प्रतियों में है जिसकी द्वितीय प्रति अभ्यर्थी को दी जायेगी, नाम-निर्देशन पत्र के साथ निक्षेप की धनराशि की रसीद के अतिरिक्त अन्य किसी शपथ पत्र की आवश्यकता अपेक्षित नहीं है। नामांकन पत्र खरीदने एवं निक्षेप की धनराशि हेतु आरक्षित श्रेणी का लाभ लेने वाले व्यक्ति को आरक्षित श्रेणी होने सम्बन्धी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
8. राज्य निर्वाचन आयोग के पत्र संख्या-1218/रा0नि0आ0-2/2633/2019 दिनांक 26.06.2019 के अनुसार नाम निर्देशन पत्र का मूल्य सामान्य श्रेणी के लिए ₹210.00(रुपये दो सौ दस) तथा अनु0 जाति, अनु0जन जाति, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए ₹105.00(रुपये एक सौ पांच) है तथा निर्वाचन में निक्षेप (जमानत) की धनराशि सामान्य प्रत्याशी के लिए ₹750.00(रुपये सात सौ पचास) तथा अनु0 जाति, अनु0जन जाति, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिला के लिए ₹375.00(रुपये तीन सौ पित्ततर) है। उक्त निर्वाचन में प्रत्याशियों द्वारा व्यय किये जाने वाली धनराशि की अधिकतम सीमा ₹15,000.00(रुपये पन्द्रह हजार) है।
9. उप प्रधान के नाम निर्देशन पत्रों की प्राप्ति, नाम निर्देशन पत्रों की जांच, नाम वापसी, निर्वाचन प्रतीक चिन्ह आवंटन, मतदान, मतगणना एवं परिणाम की घोषणा सम्बन्धित ग्राम पंचायत में निर्वाचन अधिकारी द्वारा की जायेगी।

10. मतगणना में मतों के बराबर होने की दशा में यदि कई प्रत्याशियों के मतों की संख्या बराबर हो और उनमें एक मत अधिक बढ़ा देने से उनमें कोई एक प्रत्याशी निर्वाचित घोषित हो जाने का अधिकारी हो जायेगा तो निर्वाचन अधिकारी तुरन्त उनके बीच पर्ची डालेगा और इस प्रकार की कार्यवाही करेगा मानो उस प्रत्याशी ने, जिसके हक में पर्ची निकलती है, एक और मत प्राप्त कर लिया है तथा तदनुसार परिणाम अवधारित किया जायेगा।
11. निर्वाचन के पश्चात् समस्त सील बन्द अभिलेख सहायक विकास अधिकारी (पं०)/खण्ड विकास अधिकारी के माध्यम से सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी, पंचास्थानि चुनावालय की अभिरक्षा में यथाशीघ्र हस्तगत कर दिये जायेंगे।
12. नाम निर्देशन पत्रों की बिक्री क्षेत्र पंचायत मुख्यालय पर दिनांक 19 फरवरी, 2020 से 22 फरवरी, 2020 एवं दिनांक 24 फरवरी, 2020 तथा 25 फरवरी, 2020 को पूर्वान्ह 10 बजे से 05:00 बजे तक तथा तदोपरान्त 26 फरवरी, 2020 को पूर्वान्ह 08:00 बजे से 09.30 बजे तक सम्बन्धित ग्राम पंचायत में विनिर्दिष्ट स्थान पर की जायेगी।

नितिन सिंह भदौरिया,
जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी,
(पंचायत), अल्मोड़ा।



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 16 मई, 2020 ई0 (बैशाख 26, 1942 शक सम्वत्)

भाग 8

सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि

सूचना

मैंने धार्मिक कारणों से अपना नाम कैलाश चन्द्र ठाकुर से बदलकर कैलाश चन्द रख लिया है। भविष्य में मुझे कैलाश चन्द पुत्र स्व0 श्री तारा चन्द्र ठाकुर निवासी 163 नैना देवी नं0-8 कमेटी लाईन मल्लीताल, नैनीताल के नाम से जान जाये।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

कैलाश चन्द पुत्र स्व0 श्री तारा चन्द्र ठाकुर

निवासी 163 नैना देवी नं0-8 कमेटी लाईन

मल्लीताल, नैनीताल।

कार्यालय नगरपालिका परिषद्, पिथौरागढ़

01 जनवरी, 2019 ई0

नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन व यूजर चार्ज उपविधि, 2017

पत्रांक 2236/एन0पी0/स्व0भा0मि0-यूजन चार्ज/2018-19

संक्षिप्त प्रसार एवं प्रारम्भ :-

1. यह उपविधि नगर पालिका परिषद् पिथौरागढ़ जिला-पिथौरागढ़ नगर की "नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन व यूजर चार्ज उपविधि, 2017" कहलायेगी।
2. यह उपविधि नगरपालिका परिषद् पिथौरागढ़, जिला-पिथौरागढ़ नगर के सम्पूर्ण क्षेत्र में प्रभावी होगी।
3. यह उपविधि सरकारी गजट उत्तराखण्ड में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी।

परिभाषाएँ :-

- I. "नगरीय ठोस अपशिष्ट" के अन्तर्गत औद्योगिक परिसंकटमय अपशिष्टों को छोड़कर किन्तु उपचारित जैव चिकित्सीय अपशिष्टों को सम्मिलित करते हुये ठोस या अर्द्ध ठोस के रूप से नगरीय/अधिसूचित क्षेत्रों में पैदा किया जाने वाला वाणिज्यिक तथा आवासीय अपशिष्ट आता है।
- II. "उपविधि" से अभिप्रेत उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 के उपबन्धों के अधीन गठित उपविधि से है।
- III. "नगर पालिका" से अभिप्रेत संविधान के अनुच्छेद 243 (थ) के खण्ड 7 के उपखण्ड (ग) के अधीन किसी नगर के संगठित नगर पालिका परिषद् पिथौरागढ़, जिला-पिथौरागढ़ से है।
- IV. "अधिशाली अधिकारी" से अभिप्रेत उ0प्र0 नगरपालिका अधिनियम 1916 के अन्तर्गत पालिका केन्द्रीयित सेवा नियमावली, 1966 के अधीन नियुक्त अधिशाली अधिकारी से है।
- V. "सफाई निरीक्षक" के अभिप्रेत नगरपालिका परिषद् पिथौरागढ़, जिला-पिथौरागढ़ नगर में शासन द्वारा तैनात सफाई निरीक्षक से है, ऐसे अधिकारी के उपलब्ध न होने की स्थिति में नगर पालिका के उस अधिकारी/कर्मचारी से हैं, जो उस पद के कार्यभार के लिए शासन नगर पालिका बोर्ड या अधिशाली अधिकारी द्वारा अधिकृत किया गया है।
- VI. "निरीक्षण अधिकारी" का अभिप्रेत अधिशाली अधिकारी, नगर स्वास्थ्य अधिकारी, सफाई निरीक्षक अथवा ऐसे अधिकारी/कर्मचारी से है जिन्हें समय-समय पर अधिशाली अधिकारी के आदेश से निरीक्षण के लिए अधिकृत किया गया है।
- VII. "नियम" से अभिप्रेत भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं0, 648 नई दिल्ली, मंगलवार 03 अक्टूबर 2000 असाधारण अधिसूचना नई दिल्ली दिनांक 25 सितम्बर 2000 द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबन्धन और हथालन) नियम, 2000 बनाये गये से है।

- VIII. "अधिनियम" से अभिप्रेत उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम-1916' (उत्तराखण्ड में यथापवृत्त) से है।
- IX. "जीव नाशित/जैव निम्नकारणीय/जैविक अपशिष्ट" (biodegradable waste) से अभिप्रेत ऐसे अपशिष्ट पदार्थों से है सूक्ष्म जीवों द्वारा निम्नकरण किया जा सकता है, जैसे बचा हुआ खाना, सब्जी एवं फलों के छिलके फूलों-पौधों आदि के पत्ते एवं अन्य जैविक अपशिष्ट आदि।
- X. "जीव अनाशित अपशिष्ट" (Non-biodegradable waste) का अभिप्रेत ऐसे कूड़ा-कचरा सामग्री से है, जो जीव नाशित कूड़ा कचरा नहीं है और इसे अन्तर्गत प्लास्टिक भी है।
- XI. "पुनर्चक्रणीय अपशिष्ट" (Recyclable waste) का अभिप्रेत ऐसे अपशिष्ट से है जो दोबारा किसी भी प्रकार सीधे अथवा विधि से परिवर्तित करके उसका दोबारा उपयोग किया जा सकता है, जैसे- प्लास्टिक, पौलीथीन (निर्धारित माईक्रोन के अन्दर) कागज, धातु रबड़ आदि।
- XII. "जैव चिकित्सीय अपशिष्ट" (Biomedical waste) से तात्पर्य ऐसे अपशिष्ट से है जिसका जनन मानवों व पशुओं के रोग निदान, उपचार, प्रतिरक्षीकरण के दौरान या उससे सम्बन्धित किसी अनुसंधान, क्रियाकलापों या जैविक के उत्पादन या परीक्षण के दौरान हुआ हो।
- XIII. "संग्रहण" (Collection) से अपशिष्ट के उत्पत्ति स्थल, संग्रहण, बिन्दुओं तथा किसी अन्य स्थान से ठोस अपशिष्ट को उठाया जाना अभिप्रेत है।
- XIV. "कचरा खाद बनाने" (Composting) एक ऐसी नियन्त्रित प्रक्रिया से अभिप्रेत है जिसमें कार्बनिक पदार्थ का सूक्ष्म जैवीय निम्नकरण अन्तर्लित है।
- XV. "ढहान तथा निर्माण सम्बन्धी अपशिष्ट" (Demolition and construction waste) से अभिप्रेत सन्निर्माण पुर्ननिर्माण, मरम्मत और ढहाने सम्बन्धी सक्रिया के परिणाम स्वरूप निर्माण सामग्री रोडियों ओर मलबे से उद्भूत अपशिष्ट से है।
- XVI. "व्यंयन" (Disposal) से भूजल, सतही जल तथा परिवेशी वायु गुणता को सन्दूषण से बचाने हेतु आवश्यक सावधानों से नगरीय ठोस अपशिष्ट का अन्तिम रूप से व्यंयन अभिप्रेत है।
- XVII. "भूमिकरण" (Landfilling) से भूजल सतह जल का प्रदूषण और वायु के साथ उड़ने वाली धूल, हवा के साथ उड़ने वाला कूड़ा, बदबू आग के खतरे, पक्षियों का खतरा, नाशी जीव/कृत्तक, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, ढाल अस्थिरता और कटाव के लिए संरक्षात्मक उपक्रमों के साथ डिजाईन की गई सुविधा में अपशिष्ट, ठोस अपशिष्ट का भूमि भरण पर निपटान अभिप्रेत है।
- XVIII. "निक्षालितिक" (Leachate) से वह द्रव्य अभिप्रेत है जिसका ठोस अपशिष्ट या अन्य माध्यम से रिसाव हुआ है तथा जिसने इसमें से धुलित अथवा निलम्बित पदार्थ का निष्कर्ष किया है।
- XIX. "नगर पालिका प्राधिकारी" (Municipal Authority) में म्युनिशिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपैलिटी, नगर पालिका परिषद जिसके अन्तर्गत अधिसूचना क्षेत्र, समिति (एन.ए.सी.) अथवा सुसंगत कानूनों के अन्तर्गत गठित कोई अन्य स्थानीय निकाय अभिप्रेत है, जहां नगरीय ठोस अपशिष्ट का प्रबन्धन और हथालन ऐसे किसी अभिकरण को सौंपा जाता है।

- XX. "स्थानीय प्राधिकारी" (Local Authority) का अभिप्रेत तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित नगर निगम, नगरपालिका परिषद, नगर पंचायत, क्षेत्र पंचायत या ग्राम पंचायत है।
- XXI. "नगरीय ठोस अपशिष्ट" (Municipal solid waste) के अन्तर्गत औद्योगिक परिसंकटमय (Hazardous) अपशिष्टों को छोड़कर किन्तु उपचारित जैव चिकित्सा अपशिष्टों को सम्मिलित करते हुए ठोस या अर्धठोस रूप से नगरीय/अधिसूचित क्षेत्रों में पैदा किया जाने वाला वाणिज्यिक तथा अवासीय अपशिष्ट आता है।
- XXII. "सुविधा के परिचालक" (Operator of facility) से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो नगरीय ठोस अपशिष्टों के संग्रहण, पृथक्करण, भण्डारण, परिवहन, प्रसंस्करण और निपटान की सुविधा का स्वामी या परिचालक है और इसके अन्तर्गत ऐसा कोई अधिकरण आता है जो अपने-अपने क्षेत्रों में नगरीय ठोस अपशिष्टों के प्रबन्धन एवं हथालन के लिए नगर पालिका प्राधिकारी द्वारा इस रूप से नियुक्त किया गया है। "प्रसंस्करण" से वह प्रक्रिया अभिप्रेत है, जिसके द्वारा अपशिष्ट सामाग्रियों को नये पुनः चक्रित उत्पादों में परिवर्तन किया जाता है।
- XXIII. "पुनर्चक्रण" (Recycling) से वह प्रक्रिया अभिप्रेत है जो नये उत्पादों के उत्पादन के लिए पृथक्करण सामाग्रियों का उत्पादन सामग्री में परिवर्तन करता है। जो अपने मूल उत्पादन के समान हो सकता है या नहीं भी हो सकता है।
- XXIV. "पृथक्करण" (Segregation) से नगरीय ठोस अपशिष्टों को कार्बनिक, अकार्बनिक, पुनः चक्रण योग्य और परिसंकटमय अपशिष्टों को वर्गों से अलग-अलग करना अभिप्रेत है।
- XXV. "भण्डारण" (Storage) से नगरीय ठोस अपशिष्टों के अस्थाई रूप से इस प्रकार डिब्बाबन्द किया जाना अभिप्रेत है जिससे कूड़ा-करकट, रोग वाहकों के आकर्षित करने, आवारा पशुओं तथा अत्याधिक दुर्गन्ध को रोका जा सके।
- XXVI. "परिवहन" (Transportation) से विशेष रूप से डिजाईन की गई परिवहन प्रणाली द्वारा स्वच्छता से एक स्थान से दूसरे स्थान तक नगरीय ठोस अपशिष्ट का परिवहन करना अभिप्रेत है ताकि दुर्गन्ध, कूड़ा-करकट बिखरने, रोग वाहकों की पहुँच से रोका जा सके।
4. कोई भी व्यक्ति/स्थापन (Establishment) नगरीय ठोस अपशिष्टों को नाली, सड़क गली, फुटपाथ, किसी भी खुले स्थान पर जो नगर पालिका द्वारा इस प्रयोजन के लिए निर्धारित नहीं किया गया है, न डालेगा और न डलवायेगा।
5. नगरीय ठोस अपशिष्टों के उत्पादक व्यक्ति/स्थापन अपशिष्ट उत्पादन स्थल पर कूड़ेदान रखेगा, जिसमें से एक जैव निम्नकरणीय अपशिष्ट तथा दूसरों में पुनः चक्रणीय अपशिष्ट संग्रहित करेगा।
6. नगरीय ठोस अपशिष्टों के उत्पादक व्यक्ति/स्थापन द्वारा उक्त बिन्दु 5 के अनुसार संग्रहित जैव निम्नकरणीय अपशिष्ट प्रतिदिन तथा पुनः चक्रणीय अपशिष्ट सप्ताह में एक दिन नगरपालिका के द्वार निर्धारित समय प्रक्रिया के अनुसार नगरपालिका के कर्मचारी/सुविधा प्रचालक (Operator of a facility) को देना होगा। (किन्तु जीव नाशित कूड़ा, जीव अनाशित थैले में रखकर नहीं डाला

- जायेगा) जिसके लिए अनुसूची में निर्धारित दरें जो समय-समय पर संशोधित करी जा सकेंगी के अनुसार उत्पादन व्यक्ति/स्थापन से प्रतिमाह सेवा शुल्क (User Charges) लिए जायेंगे।
7. नगरीय ठोस अपशिष्टों के उत्पादक व्यक्ति/स्थापन ढहान तथा निर्माण सम्बन्धी अपशिष्टों को उठाने के लिए नगर पालिका से सम्पर्क कर नगर पालिका द्वारा निर्धारित व्यवस्था के अनुसार ऐसे अपशिष्टों को उठाने के लिए निर्धारित दर पर सेवा शुल्क (User Charges) भुगतान करना होगा।
 8. नगरीय ठोस अपशिष्टों के उत्पादन व्यक्ति/स्थापन द्वारा जाहां तक सम्भव हो बागवानी व सभी पेड़-पौधों के कूड़े परिसर में ही कम्पोस्ट करना होगा, जहां करना संभव न हो तो नगर पालिका से सम्पर्क कर नगर पालिका द्वारा भुगतान करना होगा। किसी भी दशा में ऐसे अपशिष्टों को उठाने के लिए निर्धारित दर पर सेवा शुल्क (User Charges) भुगतान करना होगा। किसी भी दशा में ऐसे अपशिष्टों को जलाया नहीं जायेगा।
 9. नगरीय ठोस अपशिष्टों के उत्पादक व्यक्ति/स्थापन द्वारा प्रसिंस्कटमय (Hazardous) अपशिष्टों को अलग से जमा रखना होगा और पन्द्रह दिन में एक बार द्वार-द्वार (door to door) संग्रहण हेतु कर्मचारी/सुविधा प्रचालक को देना होगा।
 10. नगरीय ठोस अपशिष्टों के उत्पादक व्यक्ति/स्थापन जीव चिकित्सा अपशिष्टों का प्रबन्धन जीव-चिकित्सा अपशिष्ट (प्रबन्धन एवं हस्तन) नियम 1998 के अनुसार करेगा, बिना उपचारित जैव-चिकित्सा अपशिष्टों को नगरीय ठोस अपशिष्टों में नहीं मिलायेगा।
 11. नगरीय ठोस अपशिष्टों के उत्पादन करने वाला/हथालन करने वाला व्यक्ति/स्थापन तथा अन्य कोई भी व्यक्ति नगरीय ठोस अपशिष्ट को न जलायेगा और न ही जलवायेगा।
 12. नगरीय ठोस अपशिष्टों के उत्पादन, पृथक्करण, संग्रहण, भण्डारण परिवहन तथा व्ययन से सम्बन्धित स्थल का निरीक्षण का अधिकार निरीक्षण अधिकारी को होगा।
 13. निरीक्षण अधिकारी द्वारा स्थल पर गये नगरीय ठोस अपशिष्ट को यदि तत्काल उठाने की आवश्यकता समझी जाती है तो मासिक यूजर चार्ज के अन्तर्गत निर्धारित नहीं है को अपशिष्ट उत्पादक के द्वारा अथवा नगर पालिका/सुविधा प्रचालक तत्काल उठवाया जा सकेगा और उसके लिये स्थल पर ही यूजर चार्ज वसूल किया जा सकेगा। जिसकी रसीद अपशिष्ट उत्पादक को दी जायेगी वह धनराशि उसी दिन अथवा अगले कार्य दिवस में नगर पालिका/सुविधा प्रचालक के खाते में जमा की जायेगी।
 14. अनुसूची में दी गयी दरों में प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी जिसकी गणना ₹ 5.00 (पांच) के पूर्णांक में की जायेगी।
 15. उपविधि में लगाये जाने वाले यूजर चार्ज/सेवा शुल्क में छूट का प्राविधान नहीं होगा।
 16. यह कि उपविधि में दिये गये किसी नियम का उलंघन करने पर यदि कोई व्यक्ति या परिवार जैविक-अजैविक कूड़े का सड़क व नाली में फेंकता है, तो प्रथम बार ₹ 200.00 दूसरी बार पर ₹ 500.00 एवं तीसरी बार में ₹ 1,000.00 पैनेल्टी देनी होगी।

17. यह कि यदि कोई व्यक्ति आवासीय एवं व्यवसायी भवन निर्माण हेतु निर्माण सामग्री 24 घण्टे के अन्दर सार्वजनिक सड़क या नाली के ऊपर से नहीं हटाता है तो प्रथम बार ₹ 500.00 द्वितीय बार ₹ 1,000.00 एवं तीसरी बार में ₹ 1,500.00 की अर्थदण्ड (penalty) देनी होगी।
18. यह कि नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन से अन्तर्गत सेवा शुल्क (User Charges) की दरें निम्नवत् है।

क्र.सं	अपशिष्ट उत्पादक की श्रेणी/अपशिष्ट के प्रकार	प्रतिमाह सेवा शुल्क (User Charges) की राशि रुपये में			
		जैविक-अजैविक कूड़ा अलग-अलग सड़क तक पहुंचाने पर	मिश्रित कूड़ा सड़क तक पहुंचाने पर	जैविक-अजैविक कूड़ा घर/श्रोत पर ही अलग-अलग देने पर	जो व्यक्ति घर/श्रोत पर ही मिश्रित कूड़ा देने पर
1	गरीबी रेखा से नीचे के घर	5=00	10=00	15=00	20=00
2	मध्यम वर्ग कम आय वाले घर	10=00	15=00	20=00	25=00
3	उच्च आय वर्ग वाले घर	15=00	20=00	25=00	30=00
4	सब्जी एवं फल विक्रेता	50=00	100=00	75=00	125=00
5	रेस्टोरेन्ट	150=00	200=00	175=00	250=00
6	होटल/लाजिंग/गेस्ट हाउस	200=00	300=00	300=00	350=00
7	धर्मशाला	20=00	30=00	40=00	50=00
8	बारातघर	300=00	500=00	350=00	550=00
9	बैकरी	80=00	100=00	100=00	150=00
10	कार्यालय	50=00	100=00	50=00	75=00
11	स्कूल/शिक्षण संस्थाएं (आवासीय)	100=00	200=00	200=00	200=00
12	स्कूल/शिक्षण संस्थाएं (अनावासीय)	50=00	100=00	150=00	200=00
13	हॉस्पिटल/नर्सिंग होम (बायोमेडिकल वेस्ट को छोड़कर)	200=00	400=00	200=00	250=00
14	क्लीनिक (मेडिकल)	50=00	100=00	75=00	150=00
15	दुकान	30=00	60=00	50=00	100=00
16	फैक्ट्री (उद्योग)	200=00	400=00	300=00	450=00
17	वर्कशॉप/कबाड़ी	100=00	150=00	150=00	200=00
18	गन्ने का रस/जूस विक्रेता	50=00	100=00	125=00	150=00
19	सार्वजनिक/निजी स्थलों पर सर्कस/प्रदर्शनी/विवाह आदि प्रति आयोजन जिसमें अपशिष्ट उत्पन्न होता हो	200=00	500=00	500=00	400=00

20	ढहान तथा निर्माण सम्बन्धी अपशिष्ट	200=00	400=00	400=00	300=00
21	बड़े आवासीय प्रतिष्ठान जो उक्त सूची में नहीं है	100=00	200=00	200=00	250=00
22	ऐसे व्यवसायप्रतिष्ठान आवास जो उक्त सूची में नहीं है	100=00	200=00	200=00	250=00

उपरोक्त विवरण के अलावा धार्मिक कार्य जैसे- भण्डारा, जागरण, शोभा यात्रा/ जुलूस आदि पर उपरोक्त दरें लागू नहीं होगी।

शास्ति

उपरोक्त उपविधि का उल्लंघन उ0प्र0 नगरपालिका अधिनियम 1916 (उत्तराखण्ड में यथावृत्त) की धारा 299 (1) एवं नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियमावली, 2011 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा जो ₹ 5000.00 (₹ पांच हजार मात्र) तक हो सकेगा और जब ऐसा भंग निरंतर किया जाय, तो अग्रेतर जुर्माना किया जायेगा, जो प्रथम दोष सिद्धि के दिनांक के पश्चात ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसमें अपराधी का अपराध करते रहना सिद्ध हो, ₹ 500.00 तक हो सकेगा। यह अधिकार अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद पिथौरागढ़ में निहित होगा।

दीपक कुमार,
अधिशासी अधिकारी,
नगरपालिका परिषद, पिथौरागढ़।

राजेन्द्र सिंह रावत,
अध्यक्ष,
नगरपालिका परिषद, पिथौरागढ़।